



2026:AHC:66991

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 9967 वर्ष 2026

राम नरेश @ खुनी आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: जटा शंकर पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 69

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री जटा शंकर पांडे और राज्य के प्रतिपक्षियों के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मनोज गौतम को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक की ओर से दायर किया गया है, जिसमें मुकदमा लंबित रहने के दौरान थाना-पिनहाट, जिला आगरा में दर्ज यूपी गैंगस्टर और एंटी सोशल एक्टिविटीज (रोकथाम) अधिनियम की धारा 2/3 के तहत केस अपराध संख्या-127 वर्ष 2021 में उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक उस एकल मामले में ज़मानत पर है जो उसके खिलाफ गिरोह चार्ट में दिखाया गया है, उपरोक्त के अलावा, आवेदक के खिलाफ कोई अन्य मामला दर्ज नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि सह-आरोपी वासुदेव, मनीराम उर्फ मानिया और इंद्रपाल @ छिंगा को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-969 वर्ष 2025 में पारित दिनांक 09.03.2022, 09.05.2022 और 31.01.2022 के आदेशों द्वारा पहले ही ज़मानत दे दी गई है। , 16213 वर्ष 2022 और 966 वर्ष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2022। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक 22.09.2021 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. ततस्य विपरीत अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

5. आवेदक गैंग चार्ट में उसके खिलाफ दिखाए गए एकांत मामले में जमानत पर है, उपरोक्त के अलावा, आवेदक के खिलाफ कोई अन्य मामला दर्ज नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि सह-आरोपी वासुदेव, मनीराम उर्फ मानिया और इंद्रपाल @ छिंगा को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-969 वर्ष 20225 में पारित दिनांक 09.03.2022, 09.05.2022 और 31.01.2022 के आदेशों के माध्यम से पहले ही जमानत दे दी जा चुकी है। , 16213 वर्ष 2022 और 966 वर्ष 2022। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक 22.09.2021 से जेल में बंद है।

6. तथ्यों, प्रकृति और अभिलेखों से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, प्रस्तुत जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

7. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक- राम नरेश @ खुनी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो जमानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा: -

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।



(iii) आवेदक (i) मामले को खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगी।

(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस ज़मानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

मार्च 31, 2026

आरकेएम

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)